रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय में

आपराधिक विविध याचिका सं. 4705/2022

अजय कुमार, आयु लगभग 29 वर्ष, पिता श्री रामचंद्र प्रसाद, निवासी गाँव बोंगा, डाकघर. बरियाठ, थाना. इचक, जिला हजारीबाग, झारखंड, पिन कोड 85402

याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. गुंजन चौहान, आयु लगभग 48 वर्ष, प्रीतेश चौहान पति, निवासी 1ए ईश्वरी एन्क्लेव, स्वागत अपार्टमेंट के पास, सुकला कॉलोनी, हिनू, डाकघर एवं थाना डोरंडा, जिला रांची, पिन 834002

विरोधी पक्षः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री. आर. एन. सहाय, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री यशवर्धन, अधिवक्ता

राज्य के लिएः श्री विनीत के. वशिष्ठ विशेष लोक अभियोजक.

विरोधी पक्ष के लिएः कोई नहीं

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वाराः- दोनों पक्षों को सुना

2. हालांकि विपरीत पक्ष संख्या 2 को वैध रूप से नोटिस दिया गया है, फिर भी बार-बार कॉल करने के बावजूद याचिकाकर्ता की ओर से कोई नहीं आता है।

3. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें दिनांक 27.06.2022 का संज्ञान लेते हुए आदेश

को रद्द करने और रद्द करने का अनुरोध किया गया है जिसके द्वारा और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII के तहत, रांची ने भारतीय दंड संहिता की धारा 406,420,34 के तहत दंडनीय अपराधों और शिकायत मामला सं.5643/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही के लिए संज्ञान लिया है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची की अदालत में लंबित है।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि शिकायतकर्ता ने मेसर्स के साथ मताधिकार समझौता किया था। लाइफस्टाइल वेंचर जिसमें याचिकाकर्ता निदेशक है और शिकायतकर्ता ने मताधिकार शुल्क रु.. 40,300 /- का भुगतान किया लेकिन याचिकाकर्ता अनुभवी कर्मचारी प्रदान नहीं करके और रियायती दर पर प्रीमियम उत्पाद की आपूर्ति नहीं करके उक्त समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा और न ही टेलीमार्केटिंग या कॉल सेंटर सहायता प्रदान की और न ही उक्त सैलून के उद्घाटन के समय मशहूर हस्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित की।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस न्यायालय का ध्यान दिनांकित पूरक हलफनामे के पृष्ठ 4 की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि इसमें यह उल्लेख किया गया है कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है और शिकायतकर्ता/विरोधी पक्ष संख्या 2 ने उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि कुछ गलतफहमी के कारण, उन्होंने 2022 का शिकायत मामला दायर किया और वह शिकायत वापस लेने के लिए तैयार है। इसके बाद यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं। शिकायतकर्ता और मामले के अभियुक्त व्यक्तियों के बीच हुए समझौता ज्ञापन की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए, याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसमें याचिकाकर्ता द्वारा उक्त सैलून के उद्घाटन के समय किसी भी सेलिब्रिटी की उपस्थिति सुनिश्चित करने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया था। पक्षों के बीच विवाद मूल रूप से एक नागरिक विवाद है। याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील आगे **सरबजीत कौर बनाम पंजाब राज्य और अन्य** (2023) 5 एस. सी. सी. 360 में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, जिसमें से पैराग्राफ 13 निम्नलिखित हैः

"13. *<u>अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमानी का इरादा नहीं दिखाया जाता है। केवल वादे को पूरा करने में विफलता के आरोप पर आपराधिक कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा</u>। अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी 2 ने पहली शिकायत दर्ज किए जाने के बाद से अपने मामले में सुधार किया था जिसमें अपीलार्थी के खिलाफ कोई आरोप नहीं थे, बल्कि यह केवल संपत्ति विक्रेताओं के खिलाफ था जो बाद की शिकायतों में था कि अपीलार्थी का नाम उल्लिखित किया गया था। पहली शिकायत पर, एकमात्र अनुरोध प्रतिवादी 2 द्वारा भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए था। जब पहली*

शिकायत के आधार पर अपराध का पता चला, तो दूसरी शिकायत अपीलार्थी के खिलाफ भी आरोप लगाते हुए उन्नत संस्करण के साथ दायर की गई, जो पहले की शिकायत में नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा विचार एक नागरिक विवाद को आपराधिक में बदलना और अपीलार्थी पर कथित रूप से भुगतान की गई राशि की वापसी के लिए दबाव डालना है। आपराधिक अदालतों का उपयोग मामलों को निपटाने या दीवानी विवादों को निपटाने के लिए पक्षों पर दबाव बनाने के लिए नहीं किया जाता है। जहाँ भी आपराधिक अपराधों की सामग्री बनाई जाती है, आपराधिक अदालतों को संज्ञान लेना पड़ता है। जिस शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, वह बिक्री विलेख के पंजीकरण के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के लगभग तीन साल बाद दर्ज की गई थी। कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।" (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत करता है कि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं देता है जब तक कि लेन-देन की शुरुआत में धोखाधड़ी या बेईमान इरादा नहीं दिखाया जाता है और इस मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं है।

6. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील **विजय कुमार घई और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य** (2022) 7 एस. सी. सी. 124 में रिपोर्ट किए गए मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, जिसमें से पैराग्राफ 38 निम्नलिखित हैः

"38. *<u>इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है और नुकसान के नागरिक दायित्व को जन्म देता है।</u> तथापि, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य [हृदय रंजन प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य, (2000) 4 एस. सी. सी. 168:2000 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 786] मामले में अभिनिर्धारित किया गया है, केवल अनुबंध के उल्लंघन और धोखाधड़ी के बीच का अंतर, जो कि दंडात्माक अपराध है, बहुत महीन है। जबकि अनुबंध का उल्लंघन धोखाधड़ी के लिए आपराधिक अभियोजन को जन्म नहीं दे सकता है, धोखाधड़ी या बेईमान इरादे धोखाधड़ी के अपराध का आधार है। वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी 2 द्वारा दायर शिकायत अपीलार्थियों के बेईमान या धोखाधड़ी के इरादे का खुलासा नहीं करती है।" (जोर दिया गया)*

और प्रस्तुत करता है कि केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में एक आपराधिक अपराध नहीं है और नुकसान के नागरिक दायित्व को जन्म देता है और इस मामले में भी, आरोप, एक नागरिक उपचार के लिए कार्रवाई के कारण को जन्म देते हैं, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय दंड संहिता के दंडात्मक प्रावधानों के तहत दंडनीय अपराध नहीं है।

7. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील अगला (2022) 14 एस. सी. सी. 572 में रिपोर्ट किए गए **मितेश कुमार जे. शा बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य** के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है, जिसमें से पैराग्राफ 39 निम्नलिखित हैः

"39. यह भी देखा गयाः (इंडियन ऑयल कार्पोरेशन मामला [इंडियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड, (2006) 6 एस. सी. सी. 736: (2006) 3 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 188], एस. सी. सी. पृष्ठ 748 49, पैरा 13)

"13. जबकि इस मुद्दे पर, विशुद्ध रूप से दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की व्यावसायिक हलकों में बढ़ती प्रवृत्ति पर ध्यान देना आवश्यक है। यह स्पष्ट रूप से एक प्रचलित धारणा के कारण है कि नागरिक कानून उपचार समय लेने वाले हैं और ऋणदाताओं/लेनदारों के हितों की पर्याप्त रूप से रक्षा नहीं करते हैं।.....ऐसी धारणा भी है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह आपराधिक अभियोजन में उलझ सकता है, तो आसन्न समझौते की संभावना है। दीवानी विवादों और दावों को निपटाने का कोई भी प्रयास, जिसमें कोई आपराधिक अपराध शामिल नहीं है, आपराधिक अभियोजन के माध्यम से दबाव डालना चाहिए और हतोत्साहित किया जाना चाहिए।"

और प्रस्तुत करता है कि (2006) 6 एस. सी. सी. 736 में रिपोर्ट किए गए **इंडियन ऑयल कार्पोरेशन बनाम एन. ई. पी. सी. इंडिया लिमिटेड और अन्य** के मामले में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशुद्ध रूप से नागरिक विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने की व्यावसायिक हलकों में बढ़ती प्रवृत्ति पर इस धारणा के तहत ध्यान दिया कि यदि कोई व्यक्ति किसी तरह से आपराधिक अभियोजन में उलझ सकता है, तो आसन्न समझौते की संभावना है और प्रस्तुत करता है कि यह वास्तव में नागरिक प्रकृति का मामला है।

8. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील आगे मैसर्स उषा मार्टिन लिमिटेड बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के फैसले पर निर्भर करता है जो 2022 के आपराधिक विविध याचिका में पारित किया गया था और प्रस्तुत करता है कि उस मामले के तथ्यों में यह देखा गया था कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अप्रत्यक्ष उद्देश्य से न्यायालय की गंभीर प्रक्रिया का दुरुपयोग करने की मांग की जाती है, न्यायालय को बहुत हद तक प्रयास को विफल करना होगा और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना होगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 27.06.2022 का संज्ञान लेते हुए आदेश जिसमें और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ई XIII, रांची के तहत संज्ञान लिया गया है और शिकायत मामला सं.5643/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब

विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची की अदालत में लंबित है, को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

9. दूसरी ओर राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि निर्विवाद रूप से पक्षों के बीच एक समझौता है और विवाद निश्चित रूप से एक नागरिक स्वाद है और यह स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष संख्या 2, समझौते के परिणामस्वरूप, रुचि खो चुका है, इसलिए, राज्य को दिनांक 27.06.2022 का संज्ञान लेते हुए आदेश को रद्द करने और रद्द करने पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची ने शिकायत मामला सं.5643/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही का संज्ञान लिया है, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची की अदालत में लंबित है।

10. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि घटना की उत्पत्ति याचिकाकर्ता द्वारा अनुबंध के अपने हिस्से का कथित गैर-प्रदर्शन है, जिसे उसे अपनी कंपनी के निदेशक और शिकायतकर्ता के रूप में याचिकाकर्ता के बीच हुए समझौते के ज्ञापन को देखते हुए करना था। यह भी स्पष्ट है कि मामले को पक्षों के बीच सुलझा लिया गया है जैसा कि पूरक हलफनामे के पृष्ठ 4 पर रखे गए समझौते से स्पष्ट है और निश्चित रूप से विवाद का एक नागरिक स्वरूप है।

11. ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय का विचार है कि दिनांक 27.06.2022 का संज्ञान लेते हुए आदेश को जारी रखना, जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची के तहत शिकायत मामला सं.5643/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही का संज्ञान लिया गया है जो अब रांची के विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII की अदालत में लंबित है, वह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और यह एक उपयुक्त मामला है जहां दिनांक 27.06.2022 का संज्ञान लेने वाला आदेश जिसके तहत और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची के तहत संज्ञान लिया गया है, और शिकायत मामला सं.5643/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची की अदालत में लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है, को रद्द कर दिया जाए और खारिज कर दिया जाए।

12. तदनुसार, दिनांक 27.06.2022 का संज्ञान लेते हुए आदेश जिसमें और जहां विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची के तहत संज्ञान लिया गया है और शिकायत मामले No.5643/2022 से उत्पन्न होने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही जो अब विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट XIII, रांची की अदालत में लंबित है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, को रद्द कर दिया गया है और खारिज कर दिया गया है।

13. परिणाम में, इस आपराधिक विविध याचिका की अनुमति है।

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची (न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

दिनांक 21 फरवरी, 2024

यह अनुवाद संजय नारायण, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|